प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख पत्र

अप्रैल २०२५ • वर्ष-विंशति (२१) • अंक ०४ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०₹

24–25 अप्रैल 2025 को ब्राजील में सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय BRICS ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेन्स में भारत एवं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से प्रतिनिधित्व के पश्चात् BPMS के कार्यकारी अध्यक्ष का सम्मान करते कानपुर के कार्यकर्ता

DMRL कार्मिक संघ यूनियन के कार्यक्रम को संबोधित करते श्री एम. पी. सिंह,
उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं JCM तृतीय सदस्य श्री राधे श्याम जी

CWE AF एरिया MES असैनिक मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं से भेंट करते श्री रविन्द्र मिश्रा,
महामंत्री भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

MES वर्कर यूनियन CWE जोधपुर, राजिस्थान के कार्यकर्ताओं से बैठक करते श्री पुनीत चंद्र गुप्ता,
वित्त सचिव, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

RVC & D सहारनपुर के मधुकर पुन्ज RSS कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बैठक करते श्री तनवीर अहमद,
कार्यालय मंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

सम्पादक की कलम से

- श्री साधू सिंह

मित्रो

भारतीय मजदूर संघ के 70 वी वर्ष के अवसर पर जो भी कार्यक्रम तय किये गए आप सभी लोगों ने पूरे किया जिसके लिये आप बधाई के पात्र है। लेकिन संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये निधि संग्रह का भी कार्यक्रम था आम सदस्य से लेकर बड़े पदाधिकारियों के लिये धन संग्रह का लिये जो तय किया था वह 10वाँ हिस्सा भी पूरा नहीं किया। आप सभी इस ओर ध्यान उसका देंगे और निधि संग्रह का अपना दिया हुआ हिस्सा पूरा करेंगे।

महासंघ के द्वारा प्रतिवर्ष एक निवेदन किया जाता है कि हम सभी यूनियन अपने प्रतिष्ठानों में सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक कर्मचारियों को अपना सदस्य बनाएंगे, अभी तक कितना कार्य हो पाया इसकी समीक्षा करें और यदि अभी तक सदस्यता अभियान नहीं पूरा हुआ तो 20 मई तक अवश्य ही पूरा कर लेंगे।

यूनियन के वार्षिक विवरण को पंजीकरण हेतु रजिस्टार ट्रेड, यूनियन को अवश्य ही भेज देंगे। सम्बद्धता शुल्क समय पर जमा करने का कष्ट करेंगे।

मित्रो NPS का विरोध प्रारम्भ काल से करते करते भारत सरकार और नेशनल कॉउन्सिल के नेताओं ने एक अन्य स्किम लाकर कर्मचारियों के बीच एक नई समस्या खड़ी कर दी। इस स्कीम का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे कौन सी स्किम किसको शूट करते यह अध्ययन करना होगा जरूरी नहीं कि सभी को एक ही स्किम को चुनना चाहिये किसीके लिये NPS अच्छी हो सकती है तो किसी के लिये UPS यदि UPS में पेंशन की गारंटी है महंगाई भत्ता सहित। तो आपका जमा धन का बहुत बड़ा हिस्सा उसके हाथ से जा रहा है। NPS में पेंशन की गारंटी नही है तो उसे जमाधन का 60 प्रतिशत मिलेगा ही कर्मचारी की मृत्यु के बाद 40 प्रतिशत भी उसके परिवार को वापस मिल जाएगा अर्थात उसका पूरा कॉर्प्स उसको और परिवार को वापस मिल जाएगा। इसलिये केश टू केश हमें अध्यन करना होगा। तभी हम सही सलाह दे पाने में सफल हो सकते है।

मित्रो आठवें वेतन आयोग के सम्बंध में बहुत चर्चा है कि 200 दिन में रिपोर्ट लागू हो जाएगी। जल्दी ही पे कमीशन की अधिसूचना जारी की जा सकती है हम सभी को अपने विचार यूनियन के माध्यम से महासंघ तक यथा शीघ्र पहुंचाने का कष्ट करें।

मित्रो अपने महासंघ की अब नई पीढ़ी कार्य में है हमारी पीढ़ी का मै अंतिम कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में हूँ हमारे सभी साथी धीरे धीरे कार्य मुक्ति के साथ साथ दायित्व मुक्त भी हो चुके है। हमारे पूर्व की पीढ़ी भी सेवानीवर्त्ति हो चुके है बहुत से इस दुनिया को भी अलविदा कह चुके है वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छे से काम कर रही है और उम्मीद करते है कि आप सब संगठन को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पुरानी पीढी आज भी प्रासंगिक है उसे नजरंदाज न करके उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिये। कोई भी कार्यक्रम हो उन लोगों को नजरंदाज न करें कभी कभी उन लोगो से सम्पर्क करें और उनके अनुभव में से जो आपके काम का है उसे ग्रहण करें। पिछले दिनों सदस्यता सत्यापन में उन लोगो ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से किया और संगठन को उसका लाभ मिला सभी स्वतः सक्रिय हुए। बस हर व्यक्ति सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। इसका ध्यान रखें।

अपने महासंघ के अधिवेशन में निर्णय हुआ था कि रिटायर कर्मचारियों का संगठन बनाया जाय बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कार्यवाही चल रही है लगभग 200 सदस्य बन चुके है रजिस्ट्रेशन के बाद अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इस संगठन को मजबूत करें सभी को एक दिन इस संगठन में ही कार्य करना है यह ध्यान रखना है।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महासचिव के रूप

में वर्ष 2013 में दायित्व संभाला एक ऐसा समय था जब भारतीय मजदूर संघ ने इस संगठन को लगभग समाप्त कर दिया था। जब इसके इतिहास पर दृष्टि डाली गई इस संगठन की क्या आवश्यकता थी क्यो इसका गठन महान विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया। इसकी क्या उपलब्धियां रही। तो पता चला कि सरकारी क्षेत्र के आंदोलनों को प्रभावी करने के लिये यह परिसंघ जरूरी था। सभी महासंघ अपने अलग अलग आंदोलन करते थे जो कम प्रभावी होते थे। अपने सभी महासंघ गैर मान्यता प्राप्त थे कही पर सरकार हमारी बात को सुनने के लिये भी तैयार नहीं होती थी। वेतन आयोग के समक्ष जाना तो दूर हमारे मेमोरेंडम बमुश्किल लिए जाते थे तब मान्यवर ठेंगड़ी जी ने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ का गठन किया था। चौथा वेतन आयोग के समय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने संयुक्त आंदोलन शुरू किया हमारे आंदोलनों को देखते हुए वेतन आयोग ने हमारे ज्ञापन लिये और हमसे 4 बार वार्ता भी की। परिसंघ तबसे लगातार काम करता आ रहा है। माननीय बीएल शर्मा प्रेम पहले महामंत्री थे इस परिसंघ में मिटकरी जी, बाबू अमलदार सिंह, स्व राजदेव, श्री के एन शर्मा, स्व गिरीश अवस्थी, श्री प्रताप सिंह बिष्ट संजय सफाई, जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। और बहुत सी सफलताएं अर्जित की। जैसे सरकारी कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता था अपने संघर्षो का ही परिणाम रहा कि आज सभी कर्मचारी बोनस प्राप्त कर रहे है बोनस की सीलिंग सीमा हर बार हमारे आंदोलनों की ताकत पर ही बड़ी। पांचवे वेतन आयोग में हमारे ज्ञापन को बहुत तरजीह मिली सभी वेतन आयोग में हमे सुना गया बहुत कुछ दिलाने में हम सफल रहे। छठे सातवे में भी हमे सुना गया पुराने पेंशनरों को नए पेंशनरों के समान कुछ हद तक पेंशन दिलाने में हम सफल रहे। GENC का अपना स्वर्णिम इतिहास है। हमने NPS का विरोध प्रारम्भ से किया हम ग्रेच्यूटी, फैमली पेंशन दिलाने सरकार का शेयर बढ़वाने, कॉर्प्स से जरूरत पड़ने पर विड्राल की सुविधा दिलाने में सफल हुए। एक्स ग्रेसिया, और एक्स्ट्रा ऑर्डरनारी पेंशन दिलाने में सफल रहे आज भी हम OPS के लिये संघर्ष रत है UPS हमारी अपेक्षाओं पर भले ही न मिला लेकिन जो भी परिवर्तन हुए हम कह सकते है कि GENC का बहुत बड़ा योगदान रहा।

मित्रो 2013 में जब पुनः इसको समाप्त करने के जगह सुरु किया गया तो सीमित अधिकारो के साथ हमें महासचिव का दायित्व मिला हमने सातवें वेतन आयोग के गठन के लिये आंदोलन की शुरुआत की और गठित कराया सबसे कम समय मे लागू करने में हम सफल हुए। 2015 में हमने बोनस की लड़ाई लड़ी रैली की और उसी दिन शाम को ज्ञापन के साथ 3 साल के एरियर के साथ बोनस की घोषणा हुई पूरा देश जानता है। जब सभी संगठन यह तंज कस रहे थे कि आठवें वेतन आयोग का गठन नही होगा ऐसे में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन के लिये लगातार आंदोलन, ज्ञापन, पत्राचार किया। वेतन आयोग की घोषणा हमारे समक्ष है। कोई भी कर्मचारी विरोधी सरकारी नीति का विरोध सबसे पहले GENC ने किया। हमारे कार्यकाल के अंतिम पत्र पेंशनर के लिये है कि नए और पुराने पेंशनर में भेदभाव इसी सरकार ने समाप्त किया वह बरकरार रहना चाहिये। यूपीएस की कमियां साकार को गिनाने का काम भी GENC कर चुकी है। 2013 से लेकर 2025 तक 6 बड़ी रैली दिल्ली में 3 बार प्रदेशो की राजधानियों में और 24 आंदोलन यूनिट लेवल पर कराये गए। GENC आज सम्मान के साथ हमारे बीच मे है

आज दायित्व मुक्त होते समय मुझे यह प्रसन्नता है कि हमने हर उस कार्य को किया जो GENC को करना चाहिये था।

मैं अपनी पूरी टीम को जिसने मुझे इस काम मे योगदान दिया जैसे आशीष द्विवेदी, सुधीर त्रिपाठी, मुकेश जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपने मार्गदर्शकों का जिन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया उनमें से कई लोग इस दुनिया मे नहीं है, सम्मान सहित कृतज्ञता प्रकट करता हूं ।

याद रहे कोई मुझे दायित्वविहीन कार्य कर्ता न कहे। दायित्वमुक्त कार्य करता हूँ और कार्य मुक्त भी नहीं हूं। जबतक शरीर और बुद्धि साथ देगी कार्य करता रहूंगा।

नई टीम को बहुत बहुत बधाई और सफलता की कामना करता हूँ।

❐

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सैद्धांतिक विचार

सभार- जीवन दर्शन -दत्तोपंत ठेंगड़ी

परिचय

दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय विचारधारा, श्रमिक आंदोलन और राष्ट्रनिर्माण के क्षेत्र में एक महान विचारक, संगठनकर्ता और कार्यकर्ता रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ (BMS), स्वदेशी जागरण मंच (SJM) और भारतीय किसान संघ (BKS) जैसे अनेक संगठनों की स्थापना की। उनका संपूर्ण चिंतन भारतीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और श्रमिकों के कल्याण के इर्द–गिर्द घूमता है। उन्होंने मार्क्सवाद, पूंजीवाद और पश्चिमी विचारधाराओं की आलोचना करते हुए एक वैकल्पिक भारतीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसे वे 'संघ आधारित विचारधारा' के रूप में मानते थे।

1. भारतीयता पर आधारित राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का मानना था कि भारत एक राष्ट्र है जिसकी आत्मा उसकी संस्कृति है। राष्ट्र की उन्नति के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। उनके अनुसार, भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका निर्माण हजारों वर्षों की आध्यात्मिक साधना और सामाजिक समरसता से हुआ है।

उनका राष्ट्रवाद 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा से जुड़ा था, जो किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की समग्रता से जुड़ा है। वे मानते थे कि भारत के विकास का मार्ग भारतीय संस्कृति में ही छिपा है।

2. श्रमिकों के अधिकार और दायित्व

ठेंगड़ी जी का श्रमिक दृष्टिकोण विशिष्ट था। वे न तो श्रमिकों को सिर्फ 'मजदूर' के रूप में देखते थे और न ही उन्हें मात्र 'श्रम बेचने वाला' मानते थे। उनके अनुसार, श्रमिक 'राष्ट्र निर्माता' हैं। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में की, जो आज भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। उनका उद्देश्य श्रमिकों को वर्ग संघर्ष की बजाय सहयोग और सामंजस्य के मार्ग पर चलाना था।

वे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का भी स्मरण कराते थे। उनका नारा था:

"श्रमिक कोई वस्तु नहीं, वह एक जीवंत शक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करता है।"

3. पूंजीवाद और समाजवाद की आलोचना

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों पश्चिमी आर्थिक प्रणालियों की आलोचना की। उनका तर्क था कि दोनों ही व्यवस्थाएं भौतिकवाद पर आधारित हैं और मानवता की उपेक्षा करती हैं। पूंजीवाद जहां व्यक्ति की स्वार्थपरक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, वहीं समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलता है।

उनके अनुसार, भारत को इन दोनों व्यवस्थाओं से मुक्त रहकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप एक 'तीसरा मार्ग' अपनाना चाहिए, जिसे उन्होंने 'भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण' कहा। इस दृष्टिकोण में धर्म, नैतिकता, सामाजिक समरसता और प्रकृति के साथ संतुलन को विशेष स्थान प्राप्त है।

4. स्वदेशी की अवधारणा

दत्तोपंत ठेंगड़ी स्वदेशी विचार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी को केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवनदृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, स्वदेशी का अर्थ है दृ आत्मनिर्भरता, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, विदेशी निर्भरता से मुक्ति, और संस्कृति के अनुरूप विकास।

उन्होंने 1991 के बाद देश में लागू नव–उदारवादी नीतियों का विरोध किया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए खतरा बताया। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि जनमानस को स्वदेशी के प्रति जागरूक किया जाए।

5. सामाजिक समरसता और वर्ण व्यवस्था

ठेंगड़ी जी का मानना था कि भारतीय समाज को जातिवाद नहीं, बल्कि वर्णाश्रम धर्म ने जोड़ा है। उन्होंने जातिवाद का विरोध करते हुए समाज में समरसता की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय केवल सरकारी आरक्षण से नहीं आएगा, बल्कि सामाजिक व्यवहार में समानता लाने से आएगा।

उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति की सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का हो। उन्होंने 'सर्वजन

हिताय, सर्वजन सुखाय' को अपने विचारों का आधार बनाया।

6. आध्यात्मिक मानववाद

ठेंगड़ी जी ने 'आध्यात्मिक मानववाद' की अवधारणा दी, जो भारतीय दर्शन की जड़ से उपजा विचार है। यह मानव को केवल शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा मानता है। उनके अनुसार, विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानव का समग्र विकास दृ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृ होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "जब तक मनुष्य के भीतर की आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक समाज का वास्तविक कल्याण संभव नहीं।"

7. संगठनात्मक दृष्टिकोण

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संगठन निर्माण को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उन्होंने जीवन भर विभिन्न संगठनों को खड़ा किया दृ भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच इत्यादि। वे मानते थे कि संगठन व्यक्ति की क्षमताओं को दिशा देता है और उसे राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करता है।

उनका संगठन का सिद्धांत था दृ "नायक नहीं, कार्यप्रणाली प्रधान हो।" यानी किसी भी संगठन को व्यक्ति–आधारित नहीं, कार्य आधारित बनाना चाहिए ताकि वह स्थायित्व और प्रभावशीलता प्राप्त कर सके।

8. शिक्षा और युवा

ठेंगड़ी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करना चाहिए। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि यह अंग्रेजों की विरासत है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से विमुख है।

वे युवाओं को प्रेरित करते थे कि वे भारत की जड़ों की ओर लौटें, अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ें, और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भाग लें।

9. वैश्वीकरण की आलोचना

दत्तोपंत ठेंगड़ी वैश्वीकरण को 'आर्थिक उपनिवेशवाद' मानते थे। वे कहते थे कि वैश्वीकरण के नाम पर देश की संप्रभुता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोधी थे और मानते थे कि ये कंपनियाँ भारत के संसाधनों का दोहन करके उसे केवल उपभोक्ता बाजार बनाना चाहती हैं।

उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी के रास्ते पर चलना होगा और अपनी आर्थिक नीति को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा।

10. लेखन और विचार प्रसार

ठेंगड़ी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें उनके विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दृ

''Third Way'' (तीसरा मार्ग)

''Rashtra Jeevan ki Disha''

''Vikalp ki Khoj''

''Capitalism, Socialism and Indian Culture''

इन पुस्तकों में उन्होंने पश्चिमी आर्थिक विचारों की समीक्षा कर एक भारतीय वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया है जो आत्मनिर्भर, नैतिक, और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज की कल्पना करता है।

निष्कर्ष

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने भारत को उसकी आत्मा से जोड़ने, श्रमिकों को सम्मान दिलाने, और स्वदेशी विकास मॉडल को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। उनका जीवन एक साधक, विचारक और कर्मयोगी का था। वे केवल एक संगठनकर्ता नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक थे।

भारत की युवा पीढ़ी के लिए उनके विचार प्रेरणा का स्रोत हैं – एक ऐसे भारत की कल्पना करने और उसे साकार करने की प्रेरणा जो आत्मनिर्भर, समरस, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। ❐

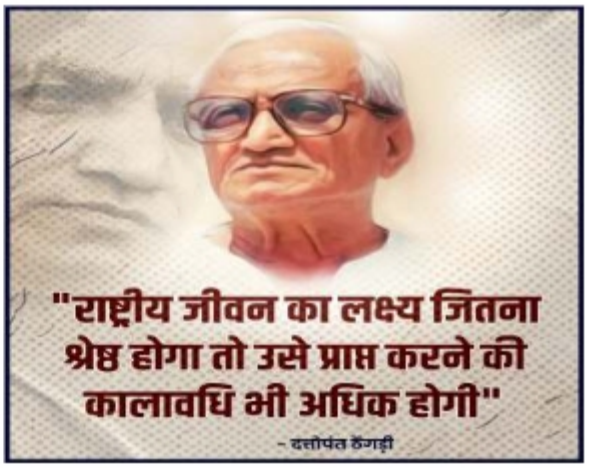

वर्ष 2025 में BRICS में श्रम संगठन की भूमिका

– शिवेन्द्र सागर शर्मा
वेब स्रोत

परिचय

वर्ष 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) श्रम संगठन कार्यक्रम ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था–"वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी और सतत शासन हेतु सहयोग को सुदृढ़ करना"।

1. कार्यक्रम की रूपरेखा

तिथि और स्थानः 25 अप्रैल 2025, ब्रासीलिया, ब्राजील

आयोजकः ब्राजील की श्रम और रोजगार मंत्रालय

सहयोगी संस्थाः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

प्रतिभागी देशः BRICS+ के 11 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात ।

2. मुख्य विषयवस्तु

क. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और श्रम का भविष्य

LEMM (Labour and Employment Ministers' Meeting) में AI के प्रभाव पर गहन चर्चा हुई। मुख्य बिंदु थेः AI का मानवीय–केंद्रित दृष्टिकोणः यह सुनिश्चित करना कि AI का उपयोग ILO के श्रम मानकों के अनुरूप हो।

श्रमिकों की सुरक्षाः AI के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

नैतिक AI विकासः AI के विकास में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना ।

ख. न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition)

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की दिशा में परिवर्तन के दौरान श्रमिकों के हितों की रक्षा पर जोर दिया गयाः

हरित नौकरियों का सृजनः पर्यावरणीय रूप से सतत नौकरियों को बढ़ावा देना।

सामाजिक सुरक्षाः परिवर्तन के दौरान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

श्रमिकों का पुनःप्रशिक्षणः नए कौशलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

3. सामाजिक संवाद और समावेशिता

कार्यक्रम में सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने पर बल दिया गयाः

सरकार, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के बीच सहयोगः नीति निर्माण में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

सामाजिक न्यायः श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और समान अवसर प्रदान करना।

वैश्विक दक्षिण में समावेशी नीतियाँः विकासशील देशों में श्रमिकों के लिए समावेशी नीतियों का विकास ।

4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की भूमिका

ILO के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हाउंग्बो ने BRICS देशों से आग्रह किया कि वे सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहाः

"हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, और BRICS देशों की भूमिका न्यायसंगत संक्रमण और AI वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण है।"

5. BRICS+ का विस्तार और सहयोग

2025 में BRICS+ में नए सदस्य देशों के शामिल होने से सहयोग का दायरा बढ़ा।

नए सदस्य देश– मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात।

सहयोग के क्षेत्रः सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए साझेदारी।

दक्षिण–दक्षिण सहयोगः विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।

6. भविष्य की दिशा

BRICS श्रम संगठन कार्यक्रम ने निम्नलिखित भविष्य की दिशा निर्धारित कीः

AI के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक मानदंडः AI के उपयोग में नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमणः पर्यावरणीय रूप से सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाना।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरणः श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।

श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमः नए कौशलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

वर्ष 2025 में आयोजित BRICS श्रम संगठन कार्यक्रम ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने दिखाया कि कैसे विकासशील देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं और एक न्यायसंगत, समावेशी, और सतत भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगला आयोजन की मेजबानी का दायित्व भारत को दिया गया है।

भारत की भूमिका और दृष्टिकोण

1. वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी : भारत ने BRICS श्रम कार्यक्रमों में AI, हरित नौकरियों, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास को अपनी प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया। भारत के श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि:

"AI और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच, भारत समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।"

2. स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ समन्वय : भारत के 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'गति शक्ति' जैसी योजनाओं को BRICS के प्रयासों से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वैश्विक सहयोग से स्थानीय रोजगार सृजन को बल मिले।

3. G–20 और BRICS की समानता : भारत की G–20 अध्यक्षता में भी जो विचार प्रमुख थे–जैसे समावेशिता, स्थिरता और नवाचारकृवे ही विचार BRICS के इस कार्यक्रम में दोहराए गए। इसका अर्थ है कि भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में लगातार अग्रसर है।

भारत को संभावित लाभ

1. AI आधारित कौशल विकास में निवेश : भारत में AI और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ठत्प्ै सहयोग के तहत नए ट्रेनिंग मॉड्यूल, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जॉब मैपिंग के अवसर मिल सकते हैं।

2. हरित रोजगार का सृजन : भारत की हरित ऊर्जा नीति जैसे 'नेशनल सोलर मिशन' और 'ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' को BRICS सहयोग से आर्थिक और तकनीकी समर्थन मिल सकता है।

3. प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा : भारत से बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों में जाते हैं। BRICS में सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के जुड़ने से प्रवासी श्रमिकों के लिए नीतिगत समन्वय की संभावना बढ़ती है।

4. महिला और युवाओं के लिए अवसर : BRICS कार्यक्रमों में लैंगिक समानता और युवाओं के लिए रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भारत जैसे जनसंख्या बहुल देश के लिए विशेष रूप से लाभदायक है।

चुनौतियाँ और सुधार के सुझाव

नीति क्रियान्वयन की गति बढ़ानी होगी

BRICS के स्तर पर बनी नीतियाँ जब तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं होंगी, तब तक इनका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा।

AI और डिजिटल डिवाइड को दूर करना होगा

ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों को AI से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ बनानी होंगी।

सामाजिक संवाद को जमीनी स्तर पर सशक्त करना

ट्रेड यूनियनों, श्रमिक संगठनों और सरकार के बीच संवाद को और पारदर्शी बनाना जरूरी है।

❐

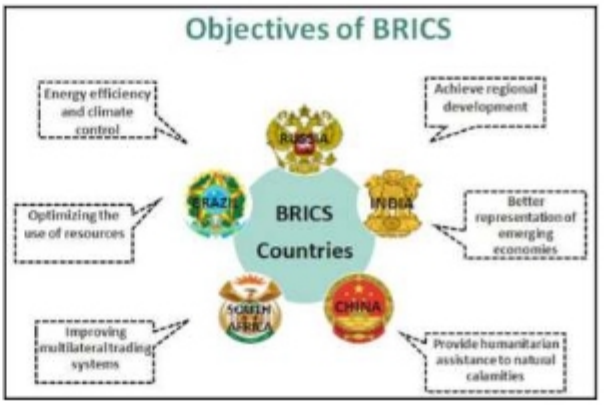

STATEMENT OF CASE FOR PAYFIXATION IN R/O RE-EMPLOYED EX-SERVICEMEN IN SPIC DRDO

INTRODUCTION

1. The pay-fixation for PBOR re-employed Ex-servicemen in SPIC (DRDO) refers to the process of determining the initial salary of a re-employed ex-serviceman, typically based on their last pay drawn before retirement from the armed forces. Specific rules and guidelines, such as those issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) and the Ministry of Defence, govern the pay fixation process.

2. When DoPT served time to time notification for the benefit for ex-servicemen, which is still not come into light or not yet initiated in SPIC for this purpose a Statement of Case prepared for better understanding to process and it will be benefit to all the PBOR re-employed ex-servicemen who had join in this organization.

3. This comprehensive Statement of Case has been prepared completely incorporating the existing rule positions on the subject. No part of this document is prepared without substantiation. All efforts has been made to present the case in a valid manner. This SOC is in full harmony with the established Government policies and that none of the contents are violative of the Ministry of Defence and D o P & T instructions on the subject

BRIEF HISTORY OF THE CASE SINCE 1912 TO TILL DATE

1. Personnel of the Armed Forces of the Indian Union are the only Government employees who retire at relatively younger ages to keep a youthful profile due to the arduous nature of their duties in hazardous and inhospitable terrains. Armed Forces Ex-Servicemen after retirement from the service seek the job opportunities due earlier at young age of retirement.

2. In view of above facts, for better understanding the root cause in r/o pay fixation for re-employed Ex-Servicemen is promulgated year wise.

2. 1912:- the British Government promulgated through CSR Civil Service Regulation (CSR, Supplement). In this CSR the Chapter XXI- Re-Employment of Pensioners, as a two section. Section I- regarding General (para 627) and in Section-II para 628 to 640, regarding following subjects and details: - "After compensation Gratuity". "Refund of pervious gratuity", "Pushtu allowance not taken into account", "Powers of the Postmaster General to re-employ a Postal Pensioner in a temporary appointment", Service of Native soldiers in the Survey Department", Salary in addition to pension", "Army Pension of soldier appointed to the Survey of India Department", "Re-employment of a Chaplain", "Military invalid Pension" and "Military Pensioners". **Reference Annexure-I.**

3. 1958:-Authority No 8(34)/Est.III/57 dated 25 Nov 1958 GoIMoF (Dept of Expenditure) after supersession of all earlier order on this subject, issued general policy on Fixation of pay of re-employed pensioners which includes Defence Estimate. In this policy important, to note is regarding increment. Sub para (b) if it is felt that the fixation of initial pay of the re-employed officer at the minimum of the prescribed pay scale will cause undue hardship, the pay may be fixed at the higher stage by allowing one increment for each year of service, which the officer has rendered before retirement. **Reference Annexure-II.**

4. 1961 :- Authority No F.12(10-Est(Spl)/61 dated 10 Oct 1961 GoIMoF (Dept of Expenditure). These refer to Rule 2(ii)(i) of the CCS (RP) Rules 1960 after consultation with Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department. The president has been pleased to decide the benefits extended in this policy, some of the key point brought to your notice that in the Sub A. sub para (B) "They will be allowed pay only in the revised scales. The pay in the revised scales will be so fixed that the emoluments (i.e., pay and dearness allowance, if any) plus the gross amount of pension / pension equivalent, do not exceed the pay reckonable as pre-retirement pay". **Reference Annexure-III.**

5. 1962 :- Authority No 7(17)-Est.III/62 dated 24 May 1962 GoIMoF (Dept of Expenditure). Regarding clarification of fixing pay and it has been clarified that the authority competent fix the pay and allowances of a military pensioner is vested with discretion to take into

account either the full amount pension or ignore any part of it. **Reference Annexure-IV**

6. 1963 :- Authority No 7(45)-Est.III/62 dated 24 May 1962 GoIMoF (Dept of Expenditure). The question raised on the OM of 1961 related to additional dearness allowance sanctioned in the OM of 1962 will be admissible to re-employed pensioners. In this regard it has been clarified above the re-employed pensioner will be entitled to draw the dearness allowance as sanctioned time to time after 1959. **Reference Annexure-V.**

7. 1963 :- Authority No.F.6(8)/E.III/63 dated 11 Apr 1963 GoIMoF (Dept of Expenditure). As a special case fixation of pay of Ex-Combatant Clerks retired/released from service in the Armed Forces on re-employment as L.D.Cs/Junior Clerks in civil posts. Their initial pay in the posts of L.D.Cs/Junior clerks may be fixed at higher stage in the scale above the minimum equal to the number of completed years of service as combatant clerk **Reference Annexure-VI.**

8. 1964 :- Authority No.F.7(34)E.III/62 dated 16 Jan 1964 GoIMoF (Dept of Expenditure). In the Second Pay Commission's recommendations of persons retiring before attaining the age of 55 the pension as shown may be ignored in fixing their pay of re-employment. **Reference Annexure-VII.**

9. 1964 :- Authority No.5(21)Est.III(B)/64 dated 15 Jun 1964 GoIMoF (Dept of Expenditure). OM regarding Fixation of pay of military pensioners re-employed in civil posts and the emoluments admissible in the Defence Service will constitute the pre-retirement pay of retired military personnel of the rank of J.C.O and below. It has also decided that for the purpose of fixation of pay re-employed military pensioners of J.C.O rank and below, the retirement pay should be taken as emoluments mentioned in the preceding paragraph plus to thirds of the dearness allowance (including dearness pay and interim relief, if any).

10. 1966 :- Authority No.F.6(8)-E.III(A)/63 dated 16 Mar 1966 GoIMoF (Dept of Expenditure). The President has been pleased to decide that these benefits should not allowed concurrently with those allowed under the Ministry's OM of 16 Jan 1964. Ex-Combatant clerks re-employed as LDCs/Junior Clerks will however, have the option to get their pay fixed under either of the two set of orders viz this Ministry's orders of 11 Apr 1963 as mended by the orders of 19 Jan 1965 or the orders of 16 Jan 1964. In the latter case, the pay on re-employed will be fixed in accordance with Ministry's OM of 25 Nov 1958 **Reference Annexure-VIII.**

11. 1968 :- Authority No.F.4(2)-E.III(A)/68 dated 19 Mar 1968 GoIMoF (Dept of Expenditure). With reference this policy Fixation of pay of Ex-Combatant Storemen retire/ released from service in the Armed Forces on re-employment as Storemen in civil posts. Extending these orders to Ex-Combatant Storemen in civil posts **Reference Annexure-VIII.**

12. 1969 :- Authority No.F.12(10)-E./69 dated 09 Jul 1969 GoIMoF (Dept of Expenditure). The reference brought forwarded regarding the Article 525 of the Civil Service Regulations and the following words shall be omitted namely:- "His pension on for service in the Civil Department will be affected by his military pension"**Reference Annexure-IX.**

13. 1970 :- Authority No.F.5(10)-Est.III(B)/64 dated 30 Dec 1970 GoIMoF (Dept of Expenditure). Fixation of pay re-employed pensioners General policy states that his pay in the new post should be fixed either under the F.Rs or under the orders contained in the OM of 25 Nov 1958 whichever is more advantageous to the person concerned **Reference Annexure-X.**

14. 1974 :- Authority No.F.67/II/16/74-Imp dated 18 Mar 1974 GoIMoF (Dept of Expenditure). 1.Applicability of CCS (RP) Rules, 1973 toRe-employed pensioners.2. Initial pay of re-employed pensioners shallbe fixed according to the provisions of Rule7 of CCS (RP) Rules, 1973.3. This OM deals with the fixation of thosepersons who were in re-employment as on 01.01.1973 only **Reference Annexure-XI.**

15. 1978 :- Authority 67/II/16/74 – IC dated 25 Feb1978 GoIMoF (Dept of Expenditure). Para 2 (ii) of the OM 1974 modified and relaxed some conditions and added somemore terms in favour of re-employed persons **Reference Annexure-XII.**

16. 1978 :- Authority 5(14)-E.III(B)/77 dated 19 Jul 1978 GoIMoF (Dept of Expenditure). Consequent on the liberalization of the pension rules and thergenral increase in pay scales on the basis of the Third pay Commissions recommendations, the question of raising the limits of ignorable in fixing their pay on re-employment. (i) in the case of pension not exceeding Rs 125/- per month the actual pension. (ii) in other case the first Rs 125/- of the pension **Reference Annexure-XIII.**

16. 1979 :-Authority G.I. M.H.A Notification No 39016/10/79/Ess(c), dated 15 Dec 1979. The Central Government have been extending the facilities to ex-servicemen and promulgated in the form of rules. These rules may be called the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979", Chapter XXIII Ex-Servicemen. A lot of facilities like reservation of vacancies, special provisions regarding age limit, special provisions regarding educational qualification, relaxed standard for selection, exemption from payment of application / examination fee, special concessions to disabled ex-servicemen, priority in appointments, relaxation in medical standards, counting of past service for eligibility in certain provisions, etc. are extended to ex-servicemen **Reference Annexure-XIV.**

17. 1983 :- Authority No.F.4(3)-E-III/82 dated 13 Dec 1983 GoIMoF (Dept of Expenditure). Fixation of pay of Civil pensioner on re-employment- Raising of limit of exemption of pension. Min of Def issued order in their OM on 08 Feb 1983. The effect that the limit of pension to ignored in fixing of pay on re-employment of Ex-Servicemen, retiring before attaining the age of 55 years, will be raised to Rs 250/- in the case of Service officer and the entire pension will be ignored in the case of personnel below Commissioned officers rank. (i) In the case of officers holding Group 'A' post at the time of their retirement, first Rs 250/- of pension. (ii) in the case of officers holding Group 'B' or lower post at the time of their retirement, the entire pension **Reference Annexure-XV.**

18. 1983:-Authority No.F.2(1)-Estt. P.I. / 83 dated 25 Jun 1984 GoIMoHAffaris (Dept of Personnel and Administrative Reforms). Fixation of pay of Incumbants released from Armed Force and re-employed in Civil Posts. It has been found in some cases that the orders were not specifically brought to notice of the individuals concerned, which has resulted in their not opting for either set of orders for their Pay Fixation within the prescribed time limit. To obviate the difficulties at the time of re-employment of ex-combatant clerk/storemen on civil posts **Reference Annexure-XVI.**

19. 1986 :- Authority No 3/1/85-Estt. (P.II) dated 31 Jul 1986 GoI Min of Perosonnel, PG & Pensions (Department personnel & Training). The orders relating to fixation of pay of reemployed pensioners are scattered in a number of office memoranda issued from time to time. The question of consolidation of the existing orders simplification of the procedure governing the initial fixation of pay. The president pleased to decide that in supersession of all the previous order on the subject. The initial fixation of pay and other benefits, on the reemployment of ex-servicemen pensioners will be governed by the Central Civil Services (Fixation of Pay on Reemployed Pensioners) **Reference Annexure-XVII.**

20. 1986 :- Authority No 3/1/85-Estt. (P.II) dated 31 Jul 1986 GoI Min of Perosonnel, PG & Pensions (Department personnel & Training). Fixation of pay of Ex-Combatant Clerks/ Storemen. The initial pay in such cases shall be fix in the time scale of the reemployed posts at a stage equivalent to the stage that would have been reached by putting in the Civil posts, the number of completed years of service rendered in the posts in the Armed Forces. The pay so fixed will be not restricted to the 'pre-retirement pay'. The fixation of pay in these cases shall be done by invoking the provisions of Fundamental Rules 27 **Reference Annexure-XVII.**

21. 1993:-Authority No AI/II/242-VI dated 15 Feb 1993 issued from C.G.D.A. This is the matter regarding furnishing of pay particulars of Military Pensioners. The MoD clarified that in case where the entire amount of pension is ignored, the initial pay on re-employment has to fixed at the minimum of the scale of the re-employed post in terms of para 4(b) (i) of DOPT OM issued on 31 Jul 1986. There is no necessity of indicating the pay drawn by the individual from the date of enrolment to the date of discharge and only particular of last pay drawn will serve the purpose **Reference Annexure-XVIII.**

22. 1994 :- Authority No 3/14/93-Estt.(Pay.II) dt 01 May 1994 GoI Min of Personnel, P.G. & Pension DOPT. Fixation of pay of re-employed pensioners in OM of 31 Jul 1986 the second sentence of para 4(b) (ii) is amended as indicated Existing Sentence "if there is no such stage in pay shall be fixed at the stage below that pay. Modified sentence "If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next above that pay **Reference Annexure-XIX.**

23. 1997 :- Authority No 3/15/94-Estt (Pay-II) dated 14 Oct 1997 GoI Min of Personnel, P.G. & Pension DOPT. The Review petition in the matter justifying Government order has also been dismissed. The

Government have examined the judgement of the Supreme Court and have decided that pay of pensioners who where in the re-employment on pay 01 Jan 1986 may be fixed accordingly may also be regulated accordingly and arrears of pay to them. Where recoveries have already been made the same may be refunded after refixing the pay **Reference Annexure-XIX.**

24. 1999 :-Authority No 3/12/97-Estt (Pay-II) dated 08 Mar 1999 GoI Min of Personnel, P.G. & Pension DOPT. The pay from the date of increment in the revised scale shall also be fixed in the accordance with the provision of Rule 7 of CCS (RP) Rules, 1997 **Reference Annexure-XX.**

25. 2008 :- Authority No 3/13/2008-Estt (Pay-II) dated 11 Nov 2008 GoI Min of PersonnelP.G. & Pension DOPT. Those Personnel / Officers who re-employed prior to 01.01.2006 and who were in employment as on 01.01.2006, their pay is to be fixed in accordance with the provisions of DoP&T OM no. 3/13/2008-Estt. (Pay-II) dated 11.11.2008 **Reference Annexure-XXI.**

26. 2010 :- Authority No 3/19/2009-Estt (Pay-II) dated 05 Apr 2010 GoI Min of PersonnelP.G. & Pension DOPT. After the introduction of the system of running pay bands and grade pays it has been amended the relevant provisions of CCS(Fixation of Pay of re-employed pensioners) Orders, 1986. Existing provision of Para 4 (b), Para 4(b)(i), Para 4(b)(ii), Para 4 (c), Para 4(d) are Proposed revised Provision of Para 4 (b), Para 4(b)(i), Para 4(b)(ii), Para 4 (c), Para 4(d) **Reference Annexure-XXII.**

27. 2010 :- Authority No 3/19/2009-Estt (Pay-II) dated 08 Nov 2010 GoI Min of PersonnelP.G. & Pension DOPT. Fixation of pay of re-employed pensioner- Treatment of Military service pay. In respect of all those Defence Officers/personnel, whose pension contains on element of MSP, that need not be deducted from the pay fixed on re-employment **Reference Annexure-XXIII.**

28. 2017 :- Authority No 3/3/2016-Estt (Pay-II) dated 01 May 2017 GoI Min of PersonnelP.G. & Pension DOPT. The question of extension of the benefit of the revised pay rules to these persons and the procedure to be followed for fixing their pay in the revised pay structure. In partial modification of the Rules 2 (2)(vii) of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016, the provisions of these rules shall apply to such persons also who were in /came into re-employment on or after 01 Jan 2016 **Reference Annexure-XXIV.**

BRIEF JUSTIFICATION

1. Government of India provides re-employment opportunities to Ex-Servicemen Officers / Other Ranks of Indian Armed Forces in various Departments / Ministries, Public Sector Organizations & Autonomous Bodies as a rehabilitation measure due to their compulsory retirement at early age. According to CCS (Fixation of Pay of re-employed Pensioners) Orders 1986 amended from time to time by the DoP&T, the re-employed Officers are allowed to draw a higher stage of initial pay in consideration with their pre-retirement pay on re-employment in such Government Organizations.

2. In case of other ranks / PBOR – Personnel Below Officer Ranks (OR/NCOs/JCOs) also, even though the provisions contained in the very same order allows for the fixation of initial pay in accordance with the pre-retirement pay of such personnel. However, the majority of the Government Departments and Ministries has miss-interpreted the existing rules in respect of the personnel below Officer Rank and has allowed drawing only the entry pay of re-employed post as applicable to fresh recruits.

3. However, the Central Public Sector organizations viz., Nationalised Banks, LIC, NIC and other PSUs have allowed to draw the higher stage of initial pay (at the stage of pre retirement pay) to re-employed ex-servicemen (OR/JCOs/NCOs). It would be pertinent to note that the Pay-fixation of ex-servicemen in Nationalized Banks, PSUs etc. are also governed by exactly the same orders issued by the DoP&T from time to time.

4. Pay fixation of the re-employed pensioners on re-employment in Central Government, including that of Officers and Personnel below Officer Rank in the Armed Forces, are being done in accordance with the CCS (Fixation of pay of re-employed pensioners) Orders, 1986, issued vide Ministry of Personnel, Public Grievances and pension, Department of Personnel Training Office Memorandum No.3/1/85-Esst. (Pay-II) dated 31.07.86, as revised from time to time.

5. The 6th Central Pay Commission, as part of its recommendations had removed the then existing pay scales with the introduction of running pay bands and grade pays system, which warranted certain

amendments in the provisions of the CCS (Fixation of pay of re-employed pensioners) Orders 1986. Accordingly, on account of introduction of running pay bands and grade pays, the relevant provisions of the above rule has been modified by the Government of India vide O. M. No. 3/192009-Estt(Pay II) dated 05.04.2010 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievance Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi.

6. The provisions for pay fixation contained in the above O. M. with respect to the Officers are quite clear. The re-employed Officers who retired before attaining the age of 55 years, the first Rs. 4000/- of the pension and pension equivalent retirement benefits will be ignored for the purpose of pay fixation. Pay of such re-employed Officers will be fixed at the same stage as the last Basic Pay drawn before retirement from the forces. The non-ignorable part of pension will be reduced from the pay so fixed. As a result, pay of such Officer are fixed at much higher than the minimum pay of re-employed post.

7. With respect to the cases of ex-servicemen who retired before attaining the age of 55 years and who held post below Commissioned Officer Rank in the Defence Forces at the time of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored. The rule says that, pay of such re-employed ex-servicemen will be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post.

8. This very rule position may be misinterpreted, the authorities to deny the legitimate fixation of pay. The authorities may be consider the scope of these terms as minimum of corresponding pay of the entry pay of the scale of the re-employed post and hence have allowed the minimum of the entry pay of the re-employed post.

9. In almost all cases of initial fixation of pay in respect of re-employed ex-servicemen, the competent authorities at various regions have adopted Rule 8 of CCS (Revised Pay) Rules 2008 to govern such fixation. In most of the cases, the authorities are not aware that the fixation of such re-employed ex-servicemen pensioners are governed by Rule 7 of CCS (RP) Rules 2008, and not by Rule 8. By adopting Rule 8, the authorities have granted only the minimum of the entry pay of the re-employed post, whereas these ex-servicemen, by virtue of Rule 7 of CCS (RP) Rules, 2008 are legally entitled to receive their pre-retirement pay in the forces, as entry pay in the present organisation.

10. It is a settled fact that Military Service Pay is applicable to all combatant ranks of the Indian Armed Forces. If the clarification of the DoPT is to be believed, then at the above three occasions also the above referrals indicates just Officers, and not Jawans! As such, it is utter dismay from the part of DoP&T to issue such a clarification that Para 3 (v) is only applicable to Officers. The nodal department cannot have double standards. The DoP&T totally ignored the fact that one class cannot be singled out for special treatment, and if so happen, it would result in breach of Article 14 of the Constitution of this Nation. The Bangalore Bench of Central Administrative Tribunal (CAT) vide it's Order dated 18.06.2014 in OA No. 1093 of 2013, has rightly exposed the double standards followed by the DoP&T and held that Para 3 (v) is applicable to both Commissioned and Non-Commissioned Officers.

11. It is not the first time that the DoP&T acts indifferent. Earlier, in a clarification to the Department of Posts on the very same subject, the DoP&T went to the extent of opining that the instructions in the 1986 Orders as well as O. M. dated 05.04.2010protection of last pay drawn at retirement'. It simply implies that the Nodal Department is confused of the difference between 'pay protection' and 'pay fixation'.

12. It is pertinent to note that Rule 16 of the very same 1986 Orders deal with the fixation of ex-combatant clerks / store men. As per Rule 16, the services rendered as Combatant Clerks and Store men in Armed Forces shall be treated as equivalent to service as Lower Division Clerks / Junior Clerks and Store men.

13. Respectively in civil posts respective of the pay drawn in those posts in the Armed forces. In such cases, advance increments are granted and the initial pay shall be fixed in the time scale of the reemployed posts at a stage equivalent to the stage that would have been reached by putting in the civil posts in the Armed forces. The pay so fixed will not be restricted to the pre-retirement pay. As such, there is a considerable increase in the initial pay of an ex-combatant clerk, who's initial pay is fixed under the Rule 16. The fixation of pay in these cases shall be done by invoking the provisions of Fundamental Rules 27.

14. Protection of Pay and Fixation of Pay are different subjects. No 'pay protection' is applicable in the Central

Government. A parliament question answered by the then Defence Minister of State Shri. Jithendra Singh is appended below:

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO-2512

ANSWERED ON-20.03.2013

Pay protection of ex servicemen on reemployment

2512 . SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA

(a) whether Government of India protects the last pay drawn by ex-servicemen on re-employment in Civil Services / Public Sector Banks / SBI / RBI / LIC and other autonomous bodies under Central / State Government;

(b) if so, then what are the elements / constitutes of the pay drawn by ex-servicemen during Armed forces service are being protected / reckoned / counted for their pay fixation on re-employment; and

(c) whether instructions / guidelines in this regard have been issued and being implemented by Public Sector Undertakings / P.S. Banks / SBI / LIC / RBI and other autonomous bodies of Central / State Government?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH) (a)&(b): As per the instructions issued by Department of Personnel & Training from time to time, no protection of the pay held by the Ex-Servicemen (ESM) prior to retirement is given and he is allowed to draw pay only in the prescribed pay scale / pay structure of the post in which he is re-employed.

(c)Instructions / guidelines in this regard are issued from time to time by the respective nodal administrative ministries and it is the responsibility of the respective organizations to implement the same. Instructions / guidelines regarding pay rules of the State Government and other autonomous bodies under the State Governments are issued by the respective State Governments.

In view of the above, an adequate understanding of comparison between 'protection of last pay' and 'fixation of pay' is necessary:

Sl.No.	PROTECTION OF LAST PAY	FIXATION OF PAY
1	The applicable components of last pay drawn in the previous organisation will constitute the new basic pay of re-employed post (will not include DA and other allowances).	Allowed to draw pay only in the prescribed pay scale / pay structure of the re-employed post.
2	Allowed to continue in the same pay scale as in the previous organisation.	No protection of the scale of pay / pay structure held by them in the previous organisation shall be given.
3	Past Service in the previous organisationwill be counted for the purpose of arriving pensionary benefits in the re-employed post.	Past Service will not be counted for benefits in the re-employed post. Moreover, since 01.01.2004, no statutory pension is applicable, only contributory pension (NPS) is applicable in the Central Civil Services.
4	Can continue to draw pension of the previous organisation, but no DR is applicable in the pension.	Can continue to draw pension with applicable DR in the pension.
5	Gratuity (with interest) to be surrendered to the new organisation.	Not applicable and not required.

DOCUMENT EVIDENCE FROM DIFFERENT AUTHORITIES ON PAY FIXATION

1. **Defence Accounts Department Office Manual Part-IV (Volume-V) revised edition 2013 issued under the authority of Controller General of Defence Accounts New Delhi :- Chapter XIII, Heading Payment of Dearness Relief Dearness Relief on Pension/ Family Pension.** Para 96.3 sub sub para (ii) If the pay fixed at a higher stage because of advance increments and not protection of the last pay drawn is being given, the pay should be treated as fixed at minimum only for the purpose of ignoring the entire pension and allowing Dearness Relief on pension. However, for availing this benefit, the ex-servicemen should have retired as post below commissioned officer rank (PBOR) before the attaining the age of 55 years. **Reference Appendix 'A'**

2. **Defence Accounts Department Office Manual Part-IV (Volume-V) revised edition 2014 issued under the authority of Controller General of Defence Accounts New Delhi :- Chapter VI, Sub Heading Re-employment of Class-VI and VII pensioner (Personnel Below Officer Rank) in the Armed Force.** Para 185 States that the entire pension admissible is ignored in fixing pay on re-employment in the case of those ex-servicemen who retired before attaining the age of 55 years and held posts below the rank of Commissioned Officer (PBOR) at the time of retirement. The pay on re-employment is to be fixed at the minimum of the pay scale of the post in which they are re-employed. The pay fixed at a higher stage because of advance increment and no protection of the las pay drawn is being given, the pay should be treated as fixed at minimum only for the purpose of ignoring the entire pension and allowing dearness relief. **Reference**

Appendix 'B'

3. Office of Controller General of Defence Account Palam Delhi cant vide their letter No AT/II/2455-V dated 27 Jul 2015 and Office of the controller of Defence Accounts No-1 Staff Road Secunderbad vide their letter No Paytech.4024/Ex-Servicemen pay Fix dated 04 Aug 2015. The issue has been examined and it is stated that the personnel / officers who retired from service prior to 01 Jan 2006 and re-employed before 01 Jan 2006, retired from service prior to 01 Jan 2006 and re-employed after 01 Jan 2006, who retired and re-employed after 01 Jan 2006. Pay fixation on re-employment in respect all categories of re-employed ex-servicemen. Any contradictions between the provisions of DPOT OM 11 Nov 2008 and 05 Apr 2010, the contents of DOPT OM dated 11 Nov 2008 stan amended to the extent of the contradiction. **Reference Appendix 'C'**

4. Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Pension) DraupadiGhat, Allahabd vide Circular No 179 dated 12 May 2015. Further clarified that if the pay is fixed at a higher stage because of advance increments and no protection of last pay drawn is given, the pay should be treated as fixed at minimum only for the purpose of ignoring the entire pension and allowing dearness relief on pension. For availing this benefit the ex-servicemen would have retired at post below commissioned officer Rank (PBOR) before attaining the age of 55 years. **Reference Appendix 'D'**

5. Ministry of Defence Report, Review of service and pension matters including potential Disputes, Minimizing litigation and strengthening institutional mechanisms related to Redressal of Grievance in the year 2015 :- "Hence in respect of all those defence officers/personnel, whose pension containts an element of MSP, that need not be deducted from the pay fixed on re-employment. **Reference Appendix 'E'**

6. Office of Controller General of Defence Account Palam Delhi cant vide their letter No AT/II/2455-VIdated 06 Jul 2018. Fixation/drawalof pay of re-employed persons and retired prior to 01 Jan 2016 and who have re-employed after 01 Jan 2016 and whose entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation. It is inferred that the provisions of para 8 (iii) of DOPT OM dated 01 May 2017. Hence para 3 (v) of DOPT om dated 05 Apr 2010, which is analogical to para 8(iii) of OM dated 01 May 2017, are applicable only for the pay fixation of retired Gp 'A' officers on re-employment and not for the pay fixation of PBORs on re-employment in civil post. **Reference Appendix 'F'**

JUSTIFICATION

Fixation of pay of ex-servicemen who held posts below Commissioned Officers rank in the Defense Forces on their Re-Employment in Central Government Civil Service and Posts

(Authority 1457323/21-Estt.(Pay-II) GoI Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel and Training dated 4thAug 2021.)

1. The CCS(Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986 (as revised from time to time) circulated vide Departments OM No 3/1/85Esst(Pay-II) dated 31 Jul 1986, regulated fixtion of pay of pensioner re-employed in Central Government Civil Services and Posts. As per para 4(d) of the OM dated 31 Jul 1986, in case of persons retiring before attanining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including pension equivalent of gratuity and other forms of retirement benefits) shall be ignored (that is not taken into account) for initial pay fixation to the following extent:-

(a) In the case of ex-servicemen who held posts below commissioned officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held post below Group 'A' posts at thetime of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored.

2. Para 4(b)(i) of the OM dated 31 Jul 1986 further provides that in all cases where the pension is fully ignored, initial pay on re-employment shall be fixed at the minimum of the scale of the re-employed post.

3. After implementation of CCS (Revised Pay) Rules, 2008,the Para 4 of the OM dated 31 Jul 1986 (including para 4(b)(i)), which relating to fixation of pay, were amended vide Department OM No 3/19/2009-Estt(Pay-II) dated 05 Apr 2010. In terms of the amended provision too, in case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, entire pension and pension equivalent retirement benefits, is to be ignored (that is not be taken into account) for initial pay fixation, in the case of ex-servicemen who held posts below Commissioned Officer rank in the defence forces and in the case of civilianswho held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement.

4. As per para 4(b)(i), as amended vide OM dated 05 Apr 2010, in all cases where the pension is fully ignored (that is not to be taken into account) for pay fixation, the

initial pay on re-employment shall be fixed as per entry pay in the revised pay structure of the re-emplyed post applicable in the case of direct recruits appointed on or after 01 Jan 2006 as notified vide section II Part-A of 1stSchedule to CCS (RP) Rules 2008.

5. It is further clarified that para 3(v) of this department OM No 3/19/2009 Estt(Pay-II) dated 05 Apr 2010 is regarding determination of notional pay in respect of personnel/officers who retired prior to 01 Jan 2006 and who were re-employed after 01 Jan 2006. This notional pay is required only in case of Commissioned Service Officer belonging to the Defence Forces (civilian pensioner who held Group 'A' posts at the time of their retirement) and ex-servicemen Personnel Below Officer Rank (also civilian pensioner who held below Group 'A' posts at the time of their retirement, who basic pay on re-employment is to be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement.

6. It may be noted that the notional pay in respect of ex-servicemen who held posts below commissioned officer rank in the defence forces (as also in case of civilians who held posts below Group 'A' posts) at the time of retirement before attaining the age of 55 years, is not reckoned at all while fixing the pay on re-employment. For the ex-servicemen who held posts below commissioned officer rank in the defence forces (as also in case of civilians who held posts below Group 'A' posts) at the time of retirement who retired before attaining the age of 55 years, provisions of the para 3(v) of the OM No 3/19/2009 Estt(Pay-II) dated 05 Apr 2010 are not relevant at all.

7. In case the person has retired after 55 years of age and is re-employed afterwards in Central Civil Services and Posts, his pay is to be fixed by general principle of "Pay minus Pension". The pay for this purpose is last pay drawn.

8. The Pay of the ex-servicemen and other pensioners on their re-employment is fixed vide a specific policy i.e CSR(Civil Service Regulation) on the subject. In the present case, theex-servicemen who have been re-employed in SPICand their pay hasnot been fixed as per the Government extent policy on the subject to their disadvantage and recurring financial loss each and every month.

CONCLUSION

AUTHORITY FROM THE OFFICE ON THE RINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (Fys)Kolkata, vide No Pay/Tech-1/069/XIV dated 27 Aug 2015

PAY FIXATION ON ACCOUNT OF RE-EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN

1. Methodology for fixation of pay of re-employed Ex-Servicemen who have joined Central Govt, Deptts has been stipulated vide GOI DOP&T OM No 3/1/85-Estt(P-II) dated 31 Jul 1986 as amended from time to time. The latest orders consequent upon introduction of revised pay structure under 6thCPC have been issued vide OM dt 11 Nov 2008 and OM date 05 Apr 2010.

(a) The re-employed pensioners can broadly be classified under three heads, namely:-

(i) Personnel/Officers who have retired prior to 01 Jan 2006 and re-employed in Civil post prior to 01 Jan 2006.

"In this case, the fixation of pay of the personnel/officers who were in Govt, organisation incivil posts on re-employment basis as on 01 Jan 2006 shall be guided by the provisions of DOP&T OM dated 11 Nov 2008 read with Para 3(iv) of DOP&T OM dated 05 Apr 2010.

(ii) Personnel/Officers who have retired prior to 01 Jan 2006 and re-employed in Civil posts after 01 Jan 2006.

"In this case, the fixation of pay of the personnel/officers is to be regulated as Para-3(v) of who of DOP&T OM dated 05 Apr 2010. In case of personnel who retired as PBOR Para 3(v) of OM dt 05 Apr 2010 has to read with para-4(d)(i) of OM dt 05 Apr 2010, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored.

(iii) In other cases

"In the cases of fixation of pay of the personnel/officers other than (i) & (ii) mentioned above .i.e. personnel/officers who have retired from services after 01 Jan 2006 and re-employed after 01 Jan 2006 is to be regulated as per para 4(a), 4(b)(ii), 4(b)(iii) of CCS (Fixation of pay of re-employed pensioners) Orders 1986 as amended in Para2 of OM dt 05 Apr 2010 regrding fixation of their pay on re-employment on case to case basis as applicable.

2.In this regard if may be mentioned that the fixation of pay in respect of re-employed pensioners of this deptt. Is regulated as per provisions stated above in terms of various Oms issued by GOI from time to time. However of the opinion that the procedure followed at this end is correct and in full conformity with laid down rules.

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

No.DOPT-1712555354374 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel and Training, ESTT.(Estt. Leave) dated 8th April 2025

Subject:- Leave

Department of Personnel & Training has issued various OMs from time to time in exception to the CCS (Leave) Rules 1972 applicable to Central Government Employees. The essence of these OMs has been summarized in the following paras for guidance and better understanding.

1. Grant of maximum 42 days Special Casual Leave to Organ Donors

Keeping in view the noble activity to help another human being and to promote organ donation among the Central Government employees, the Government has decided to grant a maximum of 42 days Special Casual Leave to a Central Government servant for donating their organ(s) to anotherhuman being, as a special welfare measure in public interest, notwithstanding the provision under Appendix-III of the CCS (Leave) Rules 1972 regarding grant of Special Casual Leave not exceeding30 days in any one calendar year under certain terms and conditions.

OM No: A-24011/23/2022-Estt.(Leave) Dated: 25/4/2023

2. Grant of 60 days Special Maternity Leave in case of death of a child soon after birth / stillbirth

Keeping in view the potential emotional trauma caused due to stillbirth or death of a child soon after birth, which has a far-reaching impact on the mother's life, the Government has decided to grant a Special Maternity Leave of 60 days to a female Central Government servant in case of death of a child soon after birth / stillbirth under certain terms and conditions.

OM No: 13018/1/2021-Estt.(L) Dated: 2/9/2022

3. Leave encashment to officers appointed on contract in various posts under Government

Consequent upon the decision taken by Government, officers who are appointed on contract in various posts under the Central Government are allowed to encash 10 days earned leave at their credit on the date of termination of contract, subject to the condition that for each completed year of service put in by him / her in the post in-such contract appointments. While calculating the encashment of leave in such a contract appointment, the number of days of leave for which encashment had been allowed in previous appointment, if any, under the Government shall not be taken into account.

OM No: 14028/1/2019-Estt.(L) Dated: 20/6/2019

4. Grant of Special Casual Leave for the purpose of blood donation

Consequent upon the decision taken by Government, grant of Special Casual leave for blood donation has been extended for blood donation for apheresis (blood component such as red cells, plasma, platelets etc) for four times in a year under certain conditions.

OM No: No. 13020/1/2017-Estt(L) Dated: 28/12/2017

Note: Updated CCS(Leave) Rules, 1972 may also be seen at

OM No: CCS(LEAVE) RULES 1972 Dated: 24/9/2024

❐

"The Duty must be performed, let the Efforts be successful or not, let the work be Appreciated or not. When a man's Sincerity of purpose and Capacity are proved even his enemies come to respect him"

AMBEDKAR

CONGRATULATIONS

DMRL, DRDO हैदराबाद की यूनियन में कार्यसमिति चुनाव में 09/10 सीटों पर विजय प्राप्त की

DFLU यूनियन ने अलाइंस के साथ कार्यसमिती चुनाव में 10/10 एवं कैंटीन प्रबंध समिति चुनाव में 02/02 सीटों पर विजय प्राप्त की

VRDE अहमदनगर यूनियन ने कार्यसमिती चुनाव में 06/07 सीटों पर विजय प्राप्त की

CONDOLENCES

BPMS express deepest condolences and profound grief over the tragic and cowardly terrorist attach that occurred on 22/4/25 in Pahalgam, Jammu & Kashmir, resulting in the loss of 28 innocent tourist lives and leaving several others injured.

This inhuman and barbaric act is a direct assault on peace, unity, and humanity. BPMS strongly condemns this heinous act of terror in the strongest possible terms.

We stand in solidarity with the families of the deceased in this hour of immense sorrow and pray for the speedy recovery of the injured. We also urge the Government of India to take stringent and decisive action against those responsible fro this brutal attack and ensure that such incidents do not occur in the future.

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 April 2025
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly
MONTHLY NEWS PAPER

A delegation from the Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh (BPMS), comprising the following members, met with Shri Sanjeev Kumar, IAS, Secretary (Defence Production), Ministry of Defence, Government of India, on 16.04.2025 to discuss various issues:

Shri Maruti Pawar, President
Shri Rabindra Kumar Mishra, General Secretary
Shri Mukesh Singh, Working President
Shri P. Vidyasagar, Dy. General Secretary
Shri Punit Chandra Gupta, Finance Secretary
Shri Virendra Sharma, JCM II Member

Rabindra Kumar Mishra
General Secretary

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650